

therefore banks will provide loans at competitive rates and on soft terms. Further Component-B and C provide for convergence with the schemes of Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare (DACFW), such as Agriculture Infrastructure Fund (AIF) under which loans to group of farmers are available with interest subvention of 3% for community assets used by farmers and PM-Krishi Sinchayee Yojana (KSY) under which micro irrigation systems can be obtained.

Expansion of The PM-KUSUM Scheme

The initially approved scheme aim to add solar capacity of 25.75 GW by 2022. The total central financial support provided under the scheme was over Rs. 34,000 Cr.

In the Budget for 2020-21, expansion of the scheme was announced, which was later approved by Government with inclusion of feeder level solarisation as a new variant under Component-C. With the expansion, the targeted solar capacity addition under the scheme would be 30.8 GW as per details given below:

Component	Approved Capacity	Creation of RE Capacity Targeted (GW)	CFA Including Service Charges (Rs. Cr)
Component-A	10 GW	10	3,325
Component-B	20 lakh pumps	9.6	15,912
Component-C	15 lakh pumps	11.2	14,798
Total		30.8	34,035

Implementation Status

Based on the demand received from the states, sanction has been issued during 2019-20 and 2020-21 for installation of 4909 MW capacity of small solar power plants, installation of 3.59 lakh standalone solar pumps and solarisation of over 10 lakh existing grid connected pumps.

Under Component-A, Rajasthan, Haryana and Himachal Pradesh issued LoA for installation of small solar power plants of around 750 MW capacity to over 650 applicants. Other States are at different stages of implementation including identification of distribution sub-stations, determination of tariff of solar power to be sold to DISCOMS, inviting applications, etc.

Under Component-B, State implementing agencies issued LoA to selected vendors for

installation of over 51,000 pumps. Due to COVID-19, progress was slow during the first half of 2020-21 but thereafter installation has gathered pace and, up to 31.03.2020, over 40,000 solar pumps have been reported installed in the fields.

Under Component-C, Rajasthan successfully completed solarisation of three pilot feeders of its three DISCOMs and issued LoA for individual pump solarisation of around 10000 existing grid connected pumps. Other states are at different stages of implementation including identification of feeders, determination of tariff of surplus solar power to be sold to DISCOMs, inviting applications, etc.

Under recently introduced variant of Feeder Level Solarisation, more than 43 lakh pump demands have been received from states against the sanction capacity of 15 lakh pumps. Since demand from other states are awaited, so far, 9.25 lakh pump has been allocated to states.

It is expected that installation of small solar plants, pumps and solarisation of feeder will gather pace during 2021-22.

Beneficiary Speaks

“Government has provided me a solar pump of capacity 7.5 HP for irrigation under PM-KUSUM Scheme. I am very happy with its result by getting hassle free irrigation during day time and also saving the cost of diesel. I am doing timely irrigation of my land which will increase production. I am thankful to the Government.”

Shri Raghu Nath,

Resident of village Jai Singh wala, Block Sangat,
Distt. Bhatinda



“I have installed solar pump on my land under PM-KUSUM Scheme. Now I don't have to pay the electricity bill as the pump runs on solar energy. The pump runs 8 to 10 hours during the day and it has increased agricultural yield and revenue.”

Smt. Vijyaben Vinubhai Asodariya,

Resident of village HadmatiyaKhakhara Distt.
Junagarh

“I could not afford the cost of diesel for irrigating my 1.61 ha land, and only raising pulses as rain fed crop on part of land. After installation of solar pump, I am cultivating banana and expecting a good yield. I have also installed a drip irrigation system with the solar pump.”

Shri G. Arun

Resident of village Vridhachalam in Cuddalore
District, Tamil Nadu

PM-KUSUM in News

MNRE issues norms for farmers' scheme to boost solar energy

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, July 22

THE MINISTRY OF New and Renewable Energy (MNRE) on Monday issued guidelines for rollout of the ₹34,422-crore PM-KUSUM scheme, which would encourage farmers to generate solar power in their farms and use the clean energy to replace their diesel water pumps.

The Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhayan (PM-KUSUM) scheme entails setting up of 25,750-MW solar capacity by 2022 with the total central financial support of ₹34,422 crore.

The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) in February approved the launch of the scheme with the objective of providing financial and water security. The scheme has three components. The Component-A provides for setting



up of 10,000 megawatt of decentralised ground/ stilt-mounted grid-connected solar or other renewable energy-based power plants.

The Component-B provides for installation of 17.50 lakh stand-alone solar agriculture pumps, while the Component-C envisages solarisation of 10 lakh grid-connected agriculture pumps.

The guidelines issued on Monday stated that the Component-A and Component-C will be implemented initially on a pilot mode for 1,000

megawatt (MW) capacity and one lakh grid-connected agriculture pumps, respectively, while the Component-B will be implemented in full-fledged manner with total central government support of ₹19,036.5 crore.

After the successful implementation of pilot project of Components A and C, the same shall be scaled up with necessary modifications based on the learning from the pilot phase with the total central government support of ₹15,385.5 crore, it added.

कुसुम योजना पर अब 34,000 करोड़ रुपये की लागत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने कुसुम योजना को विस्तार देते हुए इससे कुल 30,800 मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य रखा है। इस योजना पर सरकार की 34,035 करोड़ रुपये की लागत आएगी। योजना के तहत अगले दो वित्त वर्षों में कुल 35 लाख किसानों को सोलर चालित पंप स्थापित करने की सुविधा दी जाएगी। इस योजना से देश डीजल-चालित सिंचाई पंपों से मुक्ति मिलेगी और किसानों को अतिरिक्त धन अर्जित करने का भी मौका मिलेगा। कुसुम योजना के तहत सोलर ऊर्जा से सिंचाई पंप चलाने वाले किसान अपनी अतिरिक्त बिजली वापस राज्यों की वितरण इकाइयों को बेच सकेंगे और अतिरिक्त कमाई कर सकेंगे। वैसे यह योजना मार्च, 2019 में ही लागू की गई थी। लेकिन केंद्र सरकार के तहत नवीन ऊर्जा मंत्रालय ने इसका विस्तार कर वित्त वर्ष 2022-23 तक पूरा करने का लक्ष्य

अगले दो वित्त वर्षों में कुल 35 लाख किसानों को सोलर चालित पंप स्थापित करने की सुविधा दी जाएगी

रखा है।

नवीन ऊर्जा मंत्रालय की सूचना के मुताबिक पहले चरण में किसानों को दो मेगावाट तक बिजली बनाने वाले सोलर प्लांट लगाने में मदद की जाएगी। इससे कुल 10,000 मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य रखा गया है और केंद्र सरकार की तरफ से 3,325 करोड़ रुपये की मदद दी जाएगी। दूसरे चरण में 20 लाख सोलर-चालित पंप लगाए जाएंगे जिससे 9,600 मेगावाट बिजली बनेगी। तीसरे चरण में 15 लाख सोलर पंप लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार का मानना है कि कुसुम योजना किसानों की आय दोगुनी करती की दिशा में अहम दिशा निभा सकती है। सोलर-चालित पंप को स्थानीय ग्रिड से जोड़ा जाएगा।

सौर ऊर्जा ने दोगुना की किसानों की कमाई

■ **SSM रिपोर्टर**
ssm@hik.com

प्रदेश के किसान सौर ऊर्जा का उपयोग कर अपनी कमाई दोगुनी कर रहे हैं। खेती में सोलर के नए प्रयोग न सिर्फ कमाई बढ़ा रहे हैं बल्कि कई तरह की सुविधाएं भी दे रहे हैं। हाल ही में प्रदेश और केन्द्र सरकार की कई योजनाएं लागू हुईं हैं जिसके तहत किसानों को सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसमें किसानों को उपकरणों और अन्य तकनीकी परामर्श भी की जा जानकारी दी जा रही है।



दिन रात फसलों को पानी मिलने से बढ़ रहा उत्पादन

देश के बांधी पुरवाई गांव के किसान धर्मद बटारिया ने कुछ खेतीनी पानी अपने गांव में सोलर पैनल लगाकर है। धर्मद बटारो है कि पहले किसानों अपने जाने और कई बार सौर पंपच चला किसानों ने इन पानी फसल को पानी देने में बहुत परेशानी होती थी। इसको हल करने में 22 हजार रुपये का सोलर पैनल लगाकर पानी अपने खेत के कुएं से जुड़ा। इससे बास के फसलों को दिनरात पानी दे पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले किसानों का मिल हर महीने 1 हजार या इससे अधिक आता था। अब किसानों का मिल नहीं लग रहा और साल भर में 12 हजार रुपये से अधिक की फसलों की बचत भी हो पा रही है। पानी की भरपूर उपलब्धता से बांधी अधिक उत्पादन की फसलों को हुआ है, उत्पादन भी बढ़ गया है और हमें भी सुविधा हो गई है।

सीआईटी टीम सहितमनन से प्रभावी साक्षात्कार कर रहे हैं।

कुसुम योजना: जेबीवीएमएल उत्पादित सौर ऊर्जा को 3.09 रुपये प्रति यूनिट की दर से खरीदने के लिए किसानों से करेगा 25 वर्ष का करार

सोलर फार्मिंग के लिए किसानों को कम ब्याज दर पर आसानी से मिलेगा कर्ज

श्री/सिद्धलता बहू

गांव में किसानों को सोलर फार्मिंग के लिए सौर ऊर्जा लागू करके अपना आकार से उत्पादन को बढ़ाकर बनाने के अधिक आय के लिए को पूरा करने के लिए अब प्रधान दर पर आसानी मिलेगा।

किसानों को बैंक सरकार को कुसुम योजना के तहत सौर फार्मिंग के लिए ऋण और किसानों को से प्राप्त उत्पादन करने का एका साक्षर की राशि है। यह आस राशि में ऋण प्रस्ताव बनाने की दर पर मिलेगा। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा

केंद्र ने गांधी स्तुति

- केंद्र ने गांधी जयन्ती के दिन 7 से 8 प्रतिशत दर पर ऋण देना
- पूरे में कुसुम योजना के तहत 3.09 रुपये प्रति यूनिट पर 3.5 करोड़ रुपये तक ऋण



मंत्रालय ने जेबीवीएमएल से कोरा खेती को हल करने और किसानों को सौर ऊर्जा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ऋण देना शुरू किया है।

किसानों से सौर ऊर्जा खरीदने के लिए 2.5 वर्षों का समझौता कराने को बैंक खाते के रूप में भी काम आएगा। खरीदने पर सौर ऊर्जा के

दिन पूरा किसानों है, एक करण का सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बेहतर प्रस्ताव है।

किसानों को कम ब्याज दर पर आसानी से मिलेगा कर्ज

किसानों को बैंक सरकार को कुसुम योजना के तहत सौर फार्मिंग के लिए ऋण और किसानों को से प्राप्त उत्पादन करने का एका साक्षर की राशि है। यह आस राशि में ऋण प्रस्ताव बनाने की दर पर मिलेगा। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा

किसानों को कम ब्याज दर पर आसानी से मिलेगा कर्ज

किसानों को बैंक सरकार को कुसुम योजना के तहत सौर फार्मिंग के लिए ऋण और किसानों को से प्राप्त उत्पादन करने का एका साक्षर की राशि है। यह आस राशि में ऋण प्रस्ताव बनाने की दर पर मिलेगा। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा

First farm-based solar power plant comes up in Rajasthan

SPECIAL CORRESPONDENT

JAIPUR, APRIL 02, 2021 23:31 IST

UPDATED: APRIL 02, 2021 23:31 IST

It has capacity to produce 17 lakh units of electricity per year

The first farm-based solar power plant under the Prime Minister's Kisan Urja Suraksha Evum Utthan Mahabhiyan (KUSUM) scheme has come up in Jaipur district's Kotputli tehsil with a provision for production of 17 lakh units of electricity every year.

The 1 MW project has been established on 3.50 acres of farmland in Kotputli's Bhaloji village.

The new plant is also the first of the 623 farm-based solar power projects selected by the Rajasthan Renewable Energy Corporation Limited (RRECL) for generating 722 MW capacity in the State under the scheme's first phase.

MNRE scales up PM-KUSUM scheme goal to 30.8 GW of solar capacity by 2022

OUR BUREAU

New Delhi, November 9

The Ministry of New and Renewable Energy has issued an order for the scale-up and expansion of the Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthan Mahabhayan (PM-KUSUM) Scheme. The target now is to achieve enhanced solar capacity of 30.8 gigawatt (GW) by 2022 with revised Central financial support of ₹34,035 crore.

In February 2019, the Cabinet Committee on Economic Affairs had approved the launch

of the PM-KUSUM scheme. The scheme aims providing financial and water security to farmers. The scheme had aimed to add a solar capacity of 25,750 MW by 2022. The total Central financial support then supposed to be provided under the scheme was ₹34,422 crore.

The scheme now consists of three components. The first is 10,000 MW of decentralised ground mounted grid connected renewable power plants up to 2 MW. The second is installation of 20 lakh (up from 17.50 lakh) stand-alone solar



Central aid for the scheme has been revised to ₹34,035 crore

powered agriculture pumps. The third component is solarisation of 15 lakh (up from 10 lakh) grid-connected solar powered agriculture pumps.



MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING
GOVERNMENT OF INDIA